रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 490] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 28, 2017/पौष 7, 1939
No. 490] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 28, 2017/PAUSA 7, 1939

IndiaCode

सिंडिकेट बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2017

सं. 1800/0089/पीडी:आईआरडी(ओ)/आर.68.— बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 और 12 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिंडिकेट बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से सिंडिकेट बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 में आगे संशोधन हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. (1) इन विनियमों को सिंडिकेट बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 कहा जाएगा।

(2) इन विनियमों में अन्यथा जहाँ कहीं भी वर्णन दिया गया है उसे छोड़कर, यह विनियम 1 नवंबर 2007 से लागू होंगे।

2. सिंडिकेट बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 (इसके बाद उक्त विनियम के रूप में संदर्भित होगा) के विनियम 3 में, –

(i) खंड (च) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित होंगे, अर्थात् –

'(च) "परिवार" से उद्देश्य अधिकारी की पत्नी/पति, पूर्णतया आश्रित अविवाहित बच्चे (जिसमें आश्रित सौतेला तथा कानूनन गोद लिए गए बच्चे, दिव्यांग भाई या बहिन शामिल हैं) और माता-पिता से है, जो सामान्यतया अधिकारी के साथ रहते हैं और उसपर पूर्णतया आश्रित हैं।'

विवरण- इस खंड के उद्देश्य से एक बच्चे या माता-पिता या शारीरिक रूप से दिव्याङ्ग भाई-बहिन को अधिकारी पर आश्रित माना जाएगा यदि ऐसे बच्चे, माता-पिता, भाई या बहिन की मासिक आय ₹ 3,500 से अधिक न हो।

यदि माता-पिता में से किसी एक की आय ₹ 3,500 प्रतिमाह से अधिक है या माता-पिता दोनों की समग्र आय ₹ 3,500 प्रतिमाह से अधिक है, तो माता-पिता दोनों को अधिकारी पर पूर्णतया आश्रित नहीं माना जाएगा।

(ii) खंड (ण) को छोड़ दिया जाएगा।

3. उक्त विनियम के विनियम 4 में -

(i) उप- विनियम (4क) को हटा दिया जाएगा;

(ii) उप- विनियम (4क) को हटाने के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम निविष्ट किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(5) 01 नवंबर 2007 को और उसके बाद, प्रत्येक श्रेणी के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्नवत् होंगे:

(क) उच्च कार्यपालक श्रेणी :

वेतनमान VII – ₹ 46800 - 1300/4 – 52000

वेतनमान VI – ₹ 42000 - 1200/4 – 46800

(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान V – ₹ 36200 – 1000/2 – 38200 – 1100/2 - 40400

वेतनमान IV – ₹ 30600 – 900/4 – 34200– 1000/2 – 36200

(ग) मध्य प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान III – ₹ 25700 - 800/5 – 29700 - 900/2 - 31500

वेतनमान II – ₹ 19400 - 700/1 - 20100 -800/10 - 28100

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान I – ₹ 14500-600/7- 18700-700/2- 20100- 800/7-25700.

टिप्पणी : 31 अक्तूबर 2007 को लागू वेतनमानों द्वारा शासित होने वाले प्रत्येक अधिकारी का नियमन 01 नवंबर 2007 को इस उप विनियम में निर्धारित वेतनमान में प्रक्रम-दर-प्रक्रम आधार पर किया जाएगा, अर्थात् पहले प्रक्रम से तदनुरूपी प्रक्रमों पर और वेतनवृद्धियाँ, अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, सामान्यतया वार्षिक तारीख को होंगी।

(6) उप-विनियम (1), (2), (3) (4) और (5) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी श्रेणियों में अधिकारी रखना अपेक्षित है ।

4. उक्त विनियमों के विनियम 5 में,-

(क) उप-विनियम (1), में निम्नलिखित उप विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

"(1) विनियम 4 के उप-विनियम (5) के उपबंधों के अधीन, 1 नवंबर 2007 को और उस तारीख से, वेतनवृद्धियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूर की जाएगी, अर्थात् –

(क) विनियम 4 के उप-विनियम (5) में उपवर्णित वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धियां, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्यधीन वार्षिक आधार पर प्रोद्भूत होंगी और वे जिस महीने में देय होती हैं उस महीने की पहली तारीख को दी जाएगी।

(ख) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I के अधिकारी जो मध्यम प्रबंधन श्रेणी II वेतनमान में पहुँच चुके हैं, उच्च वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने पर प्रत्येक तीन वर्षों की पूर्ण सेवा के लिए चार अवरोध वेतन वृद्धि (यों) हेतु पात्र होंगे जिसमें प्रत्येक पहले दो वर्षों के लिए ₹ 800 की दर से एवं उससे अगले दो वर्षों के लिए प्रतिवर्ष ₹ 900 की दर देय होगी।

1 नवंबर 2007 को द्वितीय अवरोध वेतन वृद्धि प्राप्त होने के पश्चात, तीन वर्ष या अधिक सेवाकाल पूर्ण करने वाले अधिकारी 1 नवंबर 2007 को तीसरी अवरोध वेतन वृद्धि प्राप्त करेंगे। और एक अन्य गतिरोध वेतन वृद्धि 1 नवंबर 2008 को या उसके बाद दूसरे अवरोध वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पश्चात छह वर्ष पूर्ण करने पर प्राप्त करेंगे।

(ग) मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II के अधिकारी, जो मध्यम प्रबंधन श्रेणी III के वेतनमान में पहुँच चुके हैं, उच्च वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने पर प्रत्येक तीन वर्षों की पूर्ण सेवा के लिए ₹ 900 की तीन अवरोध वेतन वृद्धि (यों) के लिए पात्र होंगे।

1 नवंबर 2007 को पहला अवरोध वेतन वृद्धि प्राप्त होने के पश्चात, तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि पूर्ण करने वाले अधिकारी 1 नवंबर 2007 को अगली अवरोध वेतन वृद्धि प्राप्त करेंगे और उसके पश्चात अगली गतिरोध वेतन वृद्धि 1 नवंबर 2008 को या उसके बाद पहली अवरोध वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पश्चात छह वर्ष की सेवाकाल पूर्ण करने पर प्राप्त करेंगे।

आगे, यह प्रावधान किया गया है कि वास्तविक मध्यम प्रबंधन श्रेणी III पर नियुक्त या पदोन्नत अधिकारी, प्रत्येक तीन वर्षों की पूर्ण सेवा के लिए ₹ 900 की चार अवरोध वेतन वृद्धि (यों) हेतु पात्र होंगे, या:

यह प्रावधान भी किया गया है कि अधिकारी जो पहले ही दो अवरोध वेतन वृद्धियाँ प्राप्त कर चुके हैं, और 1 नवंबर 2007 को दूसरी अवरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करने के पश्चात तीन वर्षों से अधिक सेवा पूर्ण कर चुके हैं, वे 1 नवंबर 2007 को तीसरी अवरोध वेतन वृद्धि प्राप्त करेंगे और चौथी वेतन वृद्धि 1 नवंबर 2008 को/ उसके बाद दूसरी अवरोध वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पश्चात छह वर्ष पूर्ण करने पर प्राप्त करेंगे।

टिप्पणी : इस उप विनियम के अंतर्गत अगले उच्चतर वेतनमान में की गई ऐसी वेतनवृद्धियों को पदोनन्नति नहीं माना जाएगा और अधिकारियों को वास्तविक पद के विशेषाधिकार, परिलब्धियां, ड्यूटी, उत्तरदायित्व ही जारी रहेंगे।

(ख) उप विनियम (2) में,-

(i) टिप्पणी में, (ङ) खंड के पश्चात एवं नोट से पहले, निम्नलिखित उप-विनियम निविष्ट किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(च) 1 नवंबर 2007 से, अन्य बातें समान होने पर, व्यावसायिक अर्हता भत्ते की मात्रा निम्नानुसार संशोधित माना जाए :

तालिका

जिन्होंने भारतीय बैंकर संस्थान की जूनियर एसोसिएट या भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणित एसोसिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है।	(i) श्रेणी के अधिकतम पर पहुँचने के एक वर्ष पश्चात् ₹ 410 प्रतिमाह।
जिन्होंने भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट के दोनों भाग उत्तीर्ण किए हैं।	(i) श्रेणी के अधिकतम पर पहुँचने पर एक वर्ष पश्चात् ₹ 410 प्रतिमाह। (ii) श्रेणी के अधिकतम पर पहुँचने पर दो वर्ष पश्चात् ₹ 1030 प्रतिमाह।

यदि, कोई अधिकारी द्वारा अधिकतम वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के बाद भारतीय बैंकर संस्थान की जूनियर एसोसिएट या प्रमाणित एसोसिएट (कोई एक या दोनों भाग) की योग्यता प्राप्त करता है तो, उन्हें व्यावसायिक अर्हता प्राप्त करने की तारीख से व्यावसायिक अर्हता वेतन की पहली किश्त मंजूर की जाएगी और व्यावसायिक अर्हता वेतन की बाद की किश्त का निर्मोचन, इसकी पहली किश्त के निर्मोचन की तारीख से संदर्भित होगा।

आगे ऐसे मामले में, जहां अधिकारी ने उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई एक पहले ही प्राप्त कर ली है और इसके लिए कोई वेतन वृद्धि या व्यावसायिक अर्हता वेतन नहीं प्राप्त किया है, उन्हें 1 नवंबर 2007 से या ऐसी अर्हता प्राप्त करने की तारीख से, जो कोई भी उत्तरवर्ती हो, व्यावसायिक अर्हता वेतन मंजूर किया जाएगा।",

(ii) टिप्पणी में खंड (v) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(v) यदि 27 अप्रैल 2010 को किसी अधिकारी ने खंड (iv) में बताई गई अर्हताएँ पहले ही प्राप्त कर ली हैं, और ऐसी अर्हता प्राप्त करने पर किसी भी प्रकार की वेतन वृद्धि या व्यावसायिक अर्हता वेतन नहीं प्राप्त की हैं, तो उसे 1 नवंबर 2007 से या ऐसी अर्हता प्राप्त करने की तारीख से, जो कोई भी उत्तरवर्ती हो, व्यावसायिक अर्हता वेतन मंजूर किया जाएगा।",

(ग) उप विनियम (3) में,-

(i) खंड (घ) के पश्चात और टिप्पणी से पहले, निम्नलिखित खंड निविष्ट किया जाएगा, अर्थात:-

"(ङ) 1 नवंबर 2007 को और उसके बाद से, अन्य बातें समान होने पर, नियत वैयक्तिक वेतन, मकान किराया भत्ता सहित निम्नानुसार दिया जाएगा, और सेवा की पूर्ण अवधि के लिए अवरुद्ध रहेगा।

तालिका

वेतनवृद्धि घटक	01 नवंबर 2007 को वेतनवृद्धि घटक पर महंगाई भत्ता (₹)	जहां बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है वहाँ देय कुल नियत वैयक्तिक भत्ता (₹)
(क)	**(ख)**	**(ग)**
800	58	858
900	65	965
1000	72	1072
1100	79	1179
1200	86	1286
1300	94	1394",

(ii) टिप्पणी में, खंड (i) और (ii), निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(i)खंड (ख), (ग), (घ) या (ङ) में तालिका के खंड (ग) के अंतर्गत निर्दिष्ट नियत वैयक्तिक भत्ता/नियत वैयक्तिक वेतन उन अधिकारी कर्मचारियों को देय होगा जिन्हें बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है।

(ii) आवास किराया भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों को नियत वैयक्तिक भत्ता या नियत वैयक्तिक वेतन विनियम 4 के उप विनियम (2), (3) (4) या (5) में विनिर्दिष्टनुसार संबन्धित वेतनमान की अंतिम वेतन वृद्धि प्राप्त किए जाने पर संबन्धित अधिकारी द्वारा खंड (ङ) के अंतर्गत दी गई तालिका के कॉलम (क) एवं (ख) में निर्दिष्ट आहरित आवास किराया भत्ते का कुल योग होगा।",

(iii) टिप्पणी के पश्चात आनेवाले खंड (ङ) को उप विनियम (v) और खंड (v) जैसे अंकन किया गया है, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात:-

"(v) जिस अधिकारी को उपर्युक्त खंड (क) के अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि मिल चुकी है उस ऊपर खंड (ख), (ग), (घ) या (ङ) में उल्लिखित नियत वैयक्तिक भत्ते/नियत वैयक्तिक वेतन की प्रमात्रा, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात प्राप्त होगी"।

5. उपरोक्त विनियमों के विनियम 21 में,-

(i) उप-विनियम (3) में, टिप्पणी हटा दी जाएगी;

(ii) उप-विनियम (4) में, टिप्पणी हटा दी जाएगी;

(iii) उप-विनियम (4) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम और टिप्पणी निविष्ट की जाएगी, अर्थात:-

"(5) 1 नवंबर 2007 से, अखिल भारतीय औसत कामगार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960=100 पर 0.15% भुगतान के तिमाही औसत में 2836 अंकों से अधिक प्रति 4 अंकों के उतार या चढ़ाव के लिए महंगाई भत्ता देय होगा"।

टिप्पणी :- इस उप विनियम के उद्देश्य से,-

(क) महंगाई भत्ते के प्रयोजन हेतु 'वेतन' में मूल वेतन तथा अवरोध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत हैं।

(ख) विनियम 5 के उप-विनियम (2) के स्पष्टीकरण (ग), (घ), (ङ) और (च) में निर्दिष्टानुसार, व्यावसायिक अर्हता भत्ते या व्यावसायिक अर्हता वेतन को महंगाई भत्ते के लिए गिना जाएगा।

6. उपरोक्त विनियम के विनियम 22 में, उप विनियम (1) और (2) के लिए, निम्नलिखित उप विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

"(1) 01 नवंबर 2002 को या उसके बाद से,

(क) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो उससे वह जिस वेतनमान में है उसके प्रथम प्रक्रम में मूल वेतन के 1.75% के बराबर रकम या आवास हेतु मानक किराया, जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा।

(ख) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की जाती है तो वह निम्न तालिका में निर्दिष्ट दरों पर मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा, अर्थात् :

तालिका

कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानों पर होने पर	**देय मकान किराया भत्ता**
(1)	(2)
(i) प्रमुख 'ए' वर्ग के नगरों तथा समूह 'ए' के परियोजना क्षेत्र केंद्रों में	वेतन का 8.5%
(ii) क्षेत्र I के अन्य स्थान तथा समूह 'बी' के परियोजना क्षेत्र केंद्रों में	वेतन का 7.5%
(iii) अन्य स्थान	वेतन का 6.5%

परंतु, यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उसके प्रथम प्रक्रम के 1.75% से ऊपर, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया या ऊपर स्तंभ (2) के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का अधिकतम 150% देय होगा।

(2) 01.11.2002 को या उसके बाद से,-

(क) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो उससे वह जिस वेतनमान में है उसके प्रथम प्रक्रम में मूल वेतन के 1.20% के बराबर रकम या आवास हेतु मानक किराया, जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा।

(ख)यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की जाती है तो वह निम्न तालिका में निर्दिष्ट दरों के अनुसार मकान किराया भत्ता पाने के लिए पात्र होगा :-

तालिका

कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानों पर होने पर	देय मकान किराया भत्ता
(1)	(2)
(i) प्रमुख 'ए' वर्ग के नगरों तथा समूह 'ए' के परियोजना क्षेत्र केंद्रों में	वेतन का 8.5%
(ii) क्षेत्र I के अन्य स्थान तथा समूह 'बी' के परियोजना क्षेत्र केंद्रों में	वेतन का 7.5%
(iii) अन्य स्थान	वेतन का 6.5%

परंतु, यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतन मान में वह है उसके प्रथम प्रक्रम के 1.20% से ऊपर, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया या उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में दी गई दरों के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का अधिकतम 150% देय होगा।

टिप्पणी – जैसे कि वर्तमान में प्रचलित है, आवास किराया भत्ता के लिए आवास के स्वामित्व से जुड़े अधिकारियों के दावे 150 प्रतिशत तक सीमित रहेंगे।

7. उक्त विनियमों के विनियम 23 में,-

(i) उप विनियम (1) में, 1 नवंबर 2002 के अंकों, अक्षरों, और शब्दों को, 1 नवंबर 2007 के अंक, अक्षर एवं शब्द के साथ प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप विनियम (2) में, 1 नवंबर 2002 के अंकों, अक्षरों, और शब्दों को, 1 नवंबर 2007 के अंक, अक्षर एवं शब्द के साथ प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iii) उप विनियम (3) (4) और (5) में, निम्नलिखित विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(3) 1 नवंबर 2007 को या उसके बाद, यदि कोई अधिकारी, ग्रूप ए या ग्रूप बी की किसी पारियोजना क्षेत्र में सेवारत है तो, वह ग्रूप 'क' या ग्रूप 'ख' के वर्गीकरण के अनुसार क्रमशः ₹ 290 प्रतिमाह या ₹ 255 प्रतिमाह की दर से परियोजना क्षेत्र क्षतिपूरक भत्ते के लिए पात्र होगा।

(4) 1 नवंबर 2007 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण किसी शैक्षणिक वर्ष के मध्य में किया जाता है और पूर्ववर्ती स्थान पर उसके एक या अधिक बच्चे स्कूल अथवा कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो उसे दूसरे स्थान पर कार्यग्रहण करने की तिथि से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक सभी बच्चों के लिए ₹ 700 प्रति माह का मध्य शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ता

देय होगा । परंतु पूर्ववर्ती स्थान में सभी बच्चों द्वारा अध्ययन समाप्त करने पर उस भत्ते का भुगतान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा ।

(5) 1 मई 2010 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह प्रतिनियुक्ति के पद पर देय उन सभी परिलब्धियों को प्राप्त करने के लिए अपना विकल्प दे सकता है। विकल्पतः वह अपने वेतन के अतिरिक्त वेतन का 7.75%, अधिकतम ₹ 2300/- प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते ले सकता है जो उसे उसी स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने की स्थिति में मिलते ।

परंतु, यदि उसे उसकी प्रतिनियुक्ति से पूर्व उसकी तैनाती के स्थान पर ही स्थित किसी संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उसे उसके वेतन का 4% अधिकतम ₹ 1200/- प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा:

परंतु यह भी कि जिस अधिकारी को बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में, प्रतिनियुक्त किया जाता है, उसे उसके वेतन का 4% अधिकतम ₹ 1200/- प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा ।

(iv) उप विनियम (8) के लिए, निम्नलिखित विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(8) 1 नवंबर 2007 को और उसके बाद, यदि एक दिन में उसके कार्य समय में न्यूनतम 2 घंटे के लिए विखंडन किया जाता है तो उसे ₹ 165/- प्रतिमाह सेवा विखंडन भत्ता देय होगा।"

(v) उप विनियम (10) में,-

(क) 1 नवंबर 2002 के अंकों, अक्षरों, और शब्दों को, 1 नवंबर 2007 के अंक, अक्षर एवं शब्द के साथ प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) तालिका के लिए, निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

तालिका

स्थान	**दर**
1	2
(i) 1000 मीटर और उससे अधिक परंतु 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान और मडिकेरी नगर	वेतन का 2% अधिकतम ₹ 550 प्रतिमाह
(ii) 1500 मीटर और उससे अधिक परंतु 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान	वेतन का 2½ % अधिकतम ₹ 680 प्रतिमाह
(iii) 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थान	वेतनमान का 5% अधिकतम ₹ 1570 प्रतिमाह",

8. उक्त विनियम के विनियम 24 के, उप विनियम (1) के, खंड (क) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात :-

"(क) चिकित्सा व्यय:– तारीख 01 नवंबर 2007 को और उसके बाद से, कोई अधिकारी स्वयं एवं उसके परिवार के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावे खाता विवरण समर्थित स्वयं द्वारा प्रस्तुत व्यय घोषणापत्र के आधार पर पात्र होगा। यह प्रतिपूर्ति अधिकारी द्वारा दिए गए घोषणापत्र में उल्लेखित व्यय विवरण के अनुरूप की जाएगी, अर्थात:-

तालिका

श्रेणी	वार्षिक प्रतिपूर्ति सीमा
कनिष्ठ प्रबंधन और मध्य प्रबंधन श्रेणी	₹ 5100 या वास्तविक व्यय, इनमें जो भी कम हो
वरिष्ठ प्रबंधन और उच्च कार्यपालक श्रेणी	₹ 6320 या वास्तविक व्यय, इनमें जो भी कम हो

टिप्पणी –

(i) अधिकारी अनुपभोक्त चिकित्सा व्यय का संचयन कर सकता है जो उपर्युक्त अधिकतम रकम की तीन गुना रकम से अधिक न हो जाए, या;

(ii) वर्ष 2007 के लिए चिकित्सा सहायता के अधीन चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति दो महीनों अर्थात् नवंबर 2007 एवं दिसंबर 2007 के लिए आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी।

टिप्पणी :

इस विनियम के उद्देश्य के लिए :-

(i) जिन स्थितियों में अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो उन सभी मामलों में अधिकारी के लिए 100% और उसके परिवार के सदस्यों के लिए 75% तक चिकित्सालयवास के व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी, या;

(ii) 01 मई 2010 को या उसके बाद से इस विनियम के अंतर्गत किसी अधिकारी के चिकित्सालय वास व्ययों की प्रतिपूर्ति कामगार कर्मचारियों के लिए द्विपक्षीय समझौता दिनांक 27 अप्रैल 2010 के अंतर्गत दिए गए चिकित्सालयवास योजना के नियम एवं शर्तों के अनुसार होगा, बशर्ते कि वह नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित सीमा के अधीन हो, अर्थात :-

तालिका

(क)	कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I और मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II एवं III	(i) बिस्तर शुल्क स्वयं – ₹ 700/- प्रति दिन परिवार – ₹ 525/- प्रति दिन (ii) अन्य प्रभार कामगार कर्मचारियों को लागू चिकित्सालयवास योजना के अंतर्गत दी गई सीमा का 125% के मान पर
(ख)	वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान IV एवं V और उच्च कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VI एवं VII	(i) बिस्तर शुल्क स्वयं – ₹ 900/- प्रति दिन परिवार – ₹ 675/- प्रति दिन (ii) अन्य प्रभार कामगार कर्मचारियों को लागू चिकित्सालयवास योजना के अंतर्गत दी गई सीमा का 150% के मान पर

Indiacode

9. उक्त विनियमों के विनियम 25 में, उप विनियम (2) के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात :-

"(2) उपरोक्त उप-विनियम (1) से निरपेक्ष, बैंक यदि चाहे तो वह अधिकारी को आवास उपलब्ध करा सकता है जिसके लिए अधिकारी को 01 नवंबर 2007 को और उसके बाद से, अपने वेतनमान के प्रथम प्रक्रम के 1.20% के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराये का, इनमें जो भी कम हो, भुगतान करना होगा।

परंतु जहाँ ऐसे आवास पर फर्नीचर उपलब्ध कराया जाता है, वहां बैंक द्वारा अधिकारी से उसके वेतनमान, जिसमें वह रखा गया है, के प्रथम प्रक्रम के 0.25% के बराबर अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी।

परंतु, जहां बैंक द्वारा ऐसी आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है वहां बिजली, पानी, गैस और सफाई प्रभार अधिकारी द्वारा वहन किए जाएंगे।

10. उक्त विनियमों के विनियम 36 में, उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम को निविष्ट किया गया है, जो कहता है कि :-

"(3) 1 मई 2010 से, 12 महीनों की सम्पूर्ण अवधि में, हिस्टेरेक्टोमी के मामले में भी अधिकतम 45 दिनों के लिए छुट्टी मंजूर की जा सकती है।"

11. उक्त विनियमों के विनियम 41 में, उप-विनियम (4) में खंड (क) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

(क) विराम भत्ता –1 मई 2010 को और उसके बाद से, नीचे दी गई तालिका के खंड (1) में दी गई श्रेणी या वेतनमान का कोई अधिकारी प्रतिदिन खंड (2) में दी गई दरों के अनुरूप विराम भत्ता पाने का हकदार होगा, जो कहता है कि: -

तालिका

अधिकारियों की श्रेणी/वेतनमान	प्रमुख 'क' वर्ग के नगर	क्षेत्र I	अन्य स्थान
(1)	(2)		
	₹	₹	₹
वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारी	1000	800	700
वेतनमान I/II/III के अधिकारी	800	700	600

परंतु वेतनमान IV और उससे उच्च अधिकारियों के मामले में, चार महानगरों यानि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई में बाहरी कार्य के दौरान प्रतिदिन ₹ 1200/- और वेतनमान I या II या III के अधिकारियों के लिए प्रतिदिन ₹ 1000/- की दर से विराम भत्ता देय होगा।

परंतु यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 8 घंटे से कम, किंतु 4 घंटे से अधिक है तो ऊपर बताई गई दरों की आधी दर से विराम भत्ता देय होगा।

टिप्पणी – विराम भत्ता की संगणना के लिए 'प्रतिदिन' का अभिप्राय है 24 घंटे की अवधि या उसके बाद का कोई भी भाग, जिसकी गणना विमान यात्रा के मामले में रिपोर्ट करने के समय तथा अन्य मामलों में प्रस्थान के लिए नियत समय से लेकर पहुंचने के वास्तविक समय तक की जाएगी। यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 24 घंटे से कम है तो 'प्रतिदिन' से ऐसी अवधि अभिप्रेत है जो 8 घंटे से कम न हो।

12. उक्त विनियमों के विनियम 42 में, उप विनियम (3) के पश्चात, निम्नलिखित विनियम निविष्ट किए जाएंगे, अर्थात:-

" (4) 1 मई 2010 को और उसके बाद, स्थानांतरण पर जाने वाला कोई अधिकारी पैकिंग, स्थानीय परिवहन, यात्री सामान का बीमा आदि से जुड़े व्यय के लिए नीचे दी गई तालिका के अनुसार एकमुश्त राशि आहरित करने के लिए पात्र होगा :-

तालिका

श्रेणी	एकमुश्त राशि
वरिष्ठ प्रबंध और उच्च कार्यपालक	₹ 12000
कनिष्ठ प्रबंध और मध्य प्रबंध	₹ 9,000"

13. उक्त विनियमों के विनियम 44 में, उप विनियम (3) के अंतर्गत, निम्नलिखित प्रावधान को निविष्ट किए जाएंगे, अर्थात:-

" परंतु, 01 मई 2010 को और उसके बाद, कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान का कोई अधिकारी, अवकाश पर यात्रा रियायत लेते हुए न्यूनतम हवाई यात्रा किराए के लिए पात्र होगा, इस मामले में तय की गई यात्रा के लिए रेल के वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के वास्तविक या लागू किराए, जो कोई भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाएगी और मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II और मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III के लिए अवकाश पर यात्रा रियायत संबंधी मामले में, जहां दूरी 1000 कि.मी. से कम हो, यही नियम लागू होंगे।"

14. उक्त विनियमों के विनियम 45 में,-

(i) उप विनियम (1) में, निम्नलिखित प्रावधान निविष्ट किए जाएँ, अर्थात:-
"किन्तु 1 अप्रैल 2010 को और उसके बाद बैंक की सेवा में आने वाले अधिकारियों के लिए भविष्य निधि की सुविधा नहीं होगी।"

(ii) उप विनियम (3) , खंड (ख) के बाद एवं टिप्पणी से पहले, निम्नलिखित खंड निविष्ट किया जाएगा, अर्थात :-

"(ग) ऐसे अधिकारी जो अंशदायी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आते हैं और जो पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना हैं, वे अंशदायी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत जारी रहेंगे"।,

(iii) उप विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उपविनियम निविष्ट किए जाएंगे, अर्थात : -

"(4)1 अप्रैल 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवा में आने वाले अधिकारियों को परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत लिया जाएगा, जहां अधिकारी द्वारा वेतन का 10 प्रतिशत एवं महंगाई भत्ता एवं बैंक द्वारा इसी राशि का अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा अपना अधिसूचना भारत सरकार, एफ़ संख्या। 5/7/2003-ईसीबी एवं पीआर, दिनांक 22 दिसंबर 2003, जो समय समय पर संशोधन के अधीन है, के तहत यथा अधिसूचित, नई पेंशन योजना के अनुसार किया जाएगा"।

15. उक्त विनियमों की अनुसूचियों के लिए, निम्न अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

सिंडिकेट बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 की अनुसूची
(कृपया विनियम 23 का उपविनियम (2) देखें)

अधिकारी, दि. 1 नवंबर 2007 से विशेष क्षेत्रीय भत्ते, जो उसे वापस लेने तक या पूर्ण या पाक्षिक रूप से संशोधन करने के समय तक, के लिए पात्र होगा जो तालिका में निम्नवत् दर्शाया गया है, जैसे:-

तालिका

क्र सं	**क्षेत्र**	**देय भत्ते की दर (रु)**	
		₹ 14,700 से कम वेतन के लिए	**₹ 14,700 से अधिक वेतन के लिए**
1	**2**	**3**	**4**
1.	मिजोरम (क) मिजोरम का चिंपतुईपुई जिला और मिजोरम के लुंगलाई जिले के लुंगलाई शहर से 25 किलोमीटर के बाद के क्षेत्र	2000	2600
	(ख) मिजोरम के लुंगलाई शहर से 25 किलोमीटर के बाद के क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण लुंगलाई जिला	1600	2100
	(ग) मिजोरम का संपूर्ण आईजोल जिला	1200	1500
2.	**नागालैंड**	1600	2100
3.	**अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह** (क) उत्तर एवं मध्य अंडमान, छोटा अंडमान, निकोबार एवं नारकोंडम द्वीपसमूह	2000	2600
	(ख) दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	1600	2100
4.	**सिक्किम**	2000	2600
5.	**लक्षद्वीप द्वीपसमूह**	2000	2600
6.	**असम**	320	400

क्र सं	क्षेत्र	देय भत्ते की दर (रु)	
		₹ 14,700 से कम वेतन के लिए	₹ 14,700 से अधिक वेतन के लिए
1	2	3	4
7.	**मेघालय**	320	400
8.	**त्रिपुरा** (क) त्रिपुरा के दुष्कर क्षेत्र (ख) दुष्कर क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण त्रिपुरा	1600 1200	2100 1500
9.	**मणिपुर**	1200	1500
10.	**अरुणाचल प्रदेश:** (क) अरुणाचल प्रदेश के दुष्कर क्षेत्र (ख) दुष्कर क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश	2000 1600	2600 2100
11.	**जम्मू और कश्मीर :** (क) कठुआ जिला नियाबत बानी, लोही, मलहार, मछोड़ी	2000	2600
	(ख) उधमपुर जिला (i) दुडु बसंतगढ़, लांडर भामाग इलाका, 2 (ख) में सम्मिलित को छोड़कर सभी क्षेत्र। (ii) मोहरे तहसील के कंबन पक्ष से गोयल तक के क्षेत्र तथा कियासी पक्ष से अर्नास तक के क्षेत्र।	 2000 1600	 2600 2100
	(ग) डोडा जिला किश्तवार तहसील के नियाबत नवगम तथा पद्देर के इलाके (घ) लेह जिला जिले के सभी स्थान (ङ) बारामुला जिला (i) संपूर्ण गुरेज-निराबत, तंगदर उप-मंडल तथा केरन इलाका (ii) मछिल (च) पूंछ तथा रजौरी जिला: पूंछ तथा रजौरी शहर और सुंदरबनी एवं दोनों जिलों के अन्य शहरी क्षेत्रों को छोड़कर पूंछ तथा रजौरी जिले के क्षेत्र **(छ) उपर्युक्त (क) से (च) में शामिल नहीं किए गए क्षेत्र किंतु वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 कि.मी की दूरी में आनेवाले ऐसे स्थान जहाँ सीमा भत्ते के लिए राज्य सरकार द्वारा उनके कर्मचारियों को समय-समय पर पात्र घोषित किया गया है।**	2000 2000 2000 1600 1200 1200	2600 2600 2600 2100 1500 1500
12.	**हिमाचल प्रदेश** (क) चंबा जिला (i) पंगी तहसिल, भारमौर तहसील, पंचायत : बडगांव, बजोल, दओल कुगटी, नयागाम तथा टुंडा, ग्राम : ग्राम पंचायत जगत का घाटू गाँव, ग्राम पंचायत चौहता का कनरसी गाँव। (ii) भरमौर तहसील, उपरोक्त मद (i) में शामिल पंचायतों एवं गाँवों को छोड़कर।	 2000 1600	 2600 2100
	(iii) भटियाट तहसील में झंड्डु पंचायत, चुराह तहसील, डलहौजी टाउन (बनिखेत सहित)।	1200	1500
	(ख) किन्नौर जिला : (i) आश्रंग, चिटकुल तथा हांगो कुनो/चरंग पंचायत, 15/20 क्षेत्र जिसमें छोटा खंबा, नथपा तथा रुपी के ग्राम पंचायत हैं, पूह सब-डिविजन, उपर्युक्त पंचायत क्षेत्र को छोड़कर।	2000	2600

IndiaCode

क्र सं	क्षेत्र	देय भत्ते की दर (रु)	
		₹ 14,700 से कम वेतन के लिए	₹ 14,700 से अधिक वेतन के लिए
1	2	3	4
	(ii) उपर्युक्त (क) में शामिल क्षेत्र के अलावा संपूर्ण जिला	1600	2100
	(ग) कुल्लू जिला :		
	(i) निर्मांद तहसील के 15/20 क्षेत्र जिसमें खर्गा, कुशवार तथा सर्गा ग्राम पंचायत शामिल हैं।	2000	2600
	(ii) आउटर-सेराज (निर्मांद तहसील के बरौ तथा जकत-खाना के गाँवों को छोड़कर) तथा संपूर्ण जिला (पंड्रबिस के परगना तथा आउटर सेराज क्षेत्र को छोड़कर किंतु निर्मांद तहसील के बरौ एवं जगत-खाना गांव को शामिल कर)।	1200	1500
	(घ) लाहौल तथा स्पिति जिला :		
	लाहौल तथा स्पिति के संपूर्ण क्षेत्र	2000	2600
	(ङ) शिमला जिला :		
	(i) रामपुर तहसील के 15/20 क्षेत्र जिसमें कूट, लबाना-सदाना, सरपारा तथा चडी-ब्रांदा के पंचायत शामिल हैं।	2000	2600
	(ii) दोड्रा-कावर तहसिल, रामपुर का दरकली ग्राम पंचायत, काशापथ तहसील तथा मुनिश, परगना सराहान का घोरी चाइबिस	1600	2100
	(iii) चोपल तहसील तथा घोरिस, पंजगांव, पाटस्रौ, नौबिस तथा सरहन परगना का तीन कोटी, तकलेश क्षेत्र का द्योती ग्राम पंचायत, परगना बराबिस, रामपुर कस्बा तथा रामपुर तहसील के परगना रामपुर का घोरी नोग, शिमला शहर तथा उसके उपनगर (ध्राली, जटोग, कसुमपती, मशोब्रा, तारादेवी एवं टुटु)।	1200	1500
	(च) कांगड़ा जिला :	1600	2100
	(i) बड़ा भंगल तथा छोटा भंगल के क्षेत्र		
	(ii) कांगड़ा जिले का धर्मशाला शहर तथा धर्मशाला शहर में शामिल किंतु नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय – महिला आईटीआई, दारी, मेकनिकल वर्कशॉप, रामनगर, बाल कल्याण तथा शहर एवं ग्राम आयोजना कार्यालय, सकोह, लोवर सकोह का सीआरएसएफ कार्यालय, कांगड़ा दुग्ध आपूर्ति योजना, दुगियार, एचआरटीसी वर्कशॉप, सधेर, मंडल मलेरिया कार्यालय, दारी, वन निगम कार्यालय, शामनगर, चाय फैक्टरी, दारी, आईपीएच सब-डिविजन, दान, निपटान कार्यालय, शामनगर, हिनवा परियोजना, शामनगर। एचपीकेवीवी परिसर सहित कांगड़ा जिले का पालमपुर नगर एवं पालमपुर नगर में शामिल किन्तु इसकी नगरपालिका सीमा से बाहर स्थित निम्न कार्यालय,- एचपी कृषि विश्वविद्यालय परिसर,पशु विकास कार्यालय/ जर्सी फार्म, बनूरी, सेरिकल्चर कार्यालय/ इंडो-जर्मन एग्रिकल्चर वर्कशॉप/ एचपीपीडब्ल्युडी डिविजन, बुंदला, इलेक्ट्रिकल सब-डिविजन, लोहना, डीपीओ निगम, बुंदला, इलेक्ट्रिकल एपीएसईई डिविजन, घुग्गर।	1200	1500
	(छ) मंडी जिला : जोगिंदर नगर तहसील का छुहर घाटी, थुनाग की पंचायत बागड़ा, छत्री, छोटधार, गरगुशैन, गटू, गर्यास, जंजेली, जर्यार, जोहर, कलहनी, कल्वान, खोलनाल, लोथ, सिलिबागी, सोमचान, थछधार, ताची, थाना के तहसील, धरमपुर ब्लॉक की पंचायत – बिंगा, कामला, सकलाना, तन्यार तथा ताराखोला, कर्सोग तहसील के पंचायत – बलिधार, बागड़ा, गोपालपुर, खजोल, महोग, मेहूदी, मंज, पेखी, सैंज, साराहन, तेबान, सुंदरनगर तहसील की पंचायत – बोही, बटवारा, धन्यारा, पौड़ा-कोठी, सेरी, शोजा।	1200	1500

क्र सं	क्षेत्र	देय भत्ते की दर (रु)	
		₹ 14,700 से कम वेतन के लिए	₹ 14,700 से अधिक वेतन के लिए
1	2	3	4
	(ज) सिरमौर जिला : बनी पंचायत, बखाली (पाछड़ तहसील), भड़ोग, भेनेड़ी (पौंटा तहसील), बिड़ला (नाहन तहसील), डिब्बड़ (पाछड़ तहसील) और थाना कसोगा (नाहन तहसील) की पंचायत एवं थानस्गिरी ट्रैक्ट।	1200	1500
	(झ) सोलन जिला : मंगल पंचायत	1200	1500
	(ञ) हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र जो उपर्युक्त (क) से (झ) में शामिल नहीं है।	320	400
13.	**उत्तराखंड** : चमोली, पिथौड़गढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग एवं चंपावत जिले के क्षेत्र।	2000	2600"

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह विनियम, जो पूर्व प्रभावी से लागू किए गए हैं, संबन्धित बैंकों द्वारा दी गई विशिष्ट घोषणा के आधार पर सदस्य बैंको की ओर से भारतीय बैंक संघ और बैंको के सर्वोच्च स्तर अधिकारी संघ के मध्य हस्ताक्षरित संयुक्त नोट की सहमत नियम एवं शर्तों के अनुसार हैं। अतः इस प्रकार के पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नियमों व शर्तों से किसी भी व्यक्ति के हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ए स्टीवन दास, महा प्रबन्धक

[विज्ञापन-III/4/असा./362/17]

टिप्पणी : मूल विनियम भारत सरकार के राजपत्र में दि. . . . . को प्रकाशित किया गया और इसमें अनुवर्ती संशोधन निम्नांकित अधिसूचनाओं के जरिए किए गए:-

क्र.सं.	राजपत्र की अधिसूचना सं.	दिनांक
1.	16	09.06.1990
2.	16	20.04.1991
3.	23	06.06.1992
4.	29	17.07.1996
5.	44	02.11.1996
6.	47	23.11.2002
7.	24	20.06.2014

SYNDICATE BANK

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2017

No.1800/0089/PD:IRD(O)/R.68.— In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Syndicate Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Syndicate Bank (Officers') Service Regulations, 1979, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Syndicate Bnak (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2017.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of November, 2007, except as otherwise provided in these regulations.

2. In the Syndicate Bank (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3,-

(i) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-

'(f) "family" means the spouse of the officer, wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children), physically challenged brother or sister with forty per cent, or more disability and parents ordinarily residing with and wholly dependent on the officer'.

Explanation.- For the purposes of this clause a child or parent or physically challenged brother or sister shall be deemed to be dependent on the officer if the monthly income of such child, parent, brother or sister does not exceed Rs.3,500 per month.

Provided that if the income of one of the parents exceeds Rs.3,500 per month or the aggregate income of both the parents exceeds Rs.3,500 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.'

(ii) Clause (o) shall be omitted.

3. In regulation 4 of the said regulations,-

(i) sub-regulation (4A) shall be omitted;

(ii) after sub-regulation (4A) as so omitted, the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

"(5) With effect from the 1st November, 2007, the scales of pay specified against each grade shall be as under :

(a) Top Executive Grade

Scale VII = Rs.46800 – 1300/4 – 52000

Scale VI = Rs.42000 - 1200/4 – 46800

(b) Senior Management Grade

Scale V = Rs.36200 – 1000/2 – 38200 – 1100/2 - 40400

Scale IV = Rs.30600 – 900/4 – 34200– 1000/2 – 36200

(c) Middle Management Grade

Scale III = Rs.25700 - 800/5-– 29700 - 900/2 - 31500

Scale II = Rs.19400 - 700/1 - 20100 -800/10 - 28100

IndiaCode

(d) Junior Management Grade

Scale I = Rs.14500-600/7- 18700-700/2- 20100- 800/7-25700.

Explanation.-Every officer who is governed by the scales of pay in force as on the 31st October, 2007 shall be fitted in the scale of pay set out in this sub-regulation as on 1st November, 2007 on stage to stage basis, i.e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise.

(6) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3), (4) and (5) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.".

4. In regulation 5 of the said regulations, -

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation, shall be substituted, namely: -

"(1) Subject to the provisions of sub-regulation (5) of regulation 4, on and from the 1st November, 2007, the increments shall be granted subject to the following, namely: -

(a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (5) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;

(b) officers in Junior Management Grade Scale I who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale II after reaching maximum of the higher scale shall be eligible for four stagnation increments for every three completed years of service of which first two shall be Rs.800 each and next two Rs.900 each:

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the second stagnation increment as on 1st November, 2007 shall get the third stagnation increment on 1st November, 2007 and another stagnation increment on or after the 1st November, 2008 on their completion of six years after receipt of second stagnation increment;

(c) officers in Middle Management Grade Scale II who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale III after reaching maximum of higher scale shall be eligible for three stagnation increments of Rs.900 each for every three completed years of service:

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the first stagnation increment as on the 1st November, 2007 shall get the next stagnation increment with effect from the 1st November, 2007 and a subsequent stagnation increment on or after the 1st November, 2008 on their completion of six years after receipt of the first stagnation increment:

Provided further the officers appointed to or promoted in substantive Middle Management Grade Scale III, shall be eligible for four stagnation increments of Rs.900

IndiaCode

each for every three completed years of service or :

Provided also that the officers who have already received two stagnation increments and completed more than three years of service after receipt of second stagnation increment as on the 1st November, 2007 shall get the third stagnation increment on the 1st November, 2007 and the fourth stagnation increment, on or after the 1st November, 2008 on completion of six years after receipt of second stagnation increment.

Explanation.- Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.

(b) in sub-regulation (2),-

(i) in the Explanation, after clause (e) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

IndiaCode

"(f) on and from the 1st day of November, 2007, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as under:-

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.410 per month one year after reaching maximum of the Scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.410 per month after one year on reaching maximum of the Scale. (ii) Rs.1030 per month after two years on reaching maximum of the Scale;

Provided that an Officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay:

Provided further that in a case where an officer, has already acquired any of the above qualifications and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, he may be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1st November 2007 or the date of acquiring such qualification/s, whichever is later.";

(ii) in the Note, for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:-

"(v) if an officer, as on the 27th April 2010 has already acquired any of the said qualifications referred to in clause (iv) and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, he shall be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1st day of November, 2007 or the date of acquiring such qualification, whichever is later.";

(c) in sub-regulation (3),-

(i) after clause (d) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

"(e) on and from the 1st November, 2007, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:-

TABLE

Increment Component (Rs.)	Dearness Allowance as on 01.11.2007 on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
(A)	**(B)**	**(C)**
800	58	858
900	65	965
1000	72	1072
1100	79	1179
1200	86	1286
1300	94	1394",

(ii) in the Note, for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (C) of the Table under clauses (b), (c), (d) or (e) shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.

(ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (A) and (B) of the Table under clause (e) and House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2), (3), (4) or (5) of regulation 4 is earned.";

(iii) clause (e) occurring after the Note shall be renumbered as sub-clause (v) thereof and for clause (v) as so numbered, the following clause be substituted, namely:-

"(v)An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d) or (e) above, one year after reaching the maximum of the scale";

5. In regulation 21 of the said regulations, -

(i) in sub-regulation (3), the Note shall be omitted;

(ii) in sub-regulation (4), the Note shall be omitted;

(iii) after sub-regulation (4), the following sub-regulation and Note shall be inserted, namely:-

"(5) On and from the 1st day of November, 2007, dearness allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.15% of Pay.

Explanation.- For the purposes of this sub-regulation,-

(a) "pay" for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments;

(b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in Explanations (c), (d), (e) and (f) to sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance'.

6. In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulations(1) and (2), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

"(1)on and from the 1st day of November, 2002,

(a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.75 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely:

TABLE

Where the place of work is in		HRA payable shall be
(1)		(2)
(i)	Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
(ii)	Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii)	Other places	6.5% of Pay:

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.75 per cent of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above Table.

(2) on and from the 1st day of November, 2007, -

(a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.20 per

IndiaCode

cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;

(b)where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely: -

TABLE

Where the place of work is in		HRA payable shall be
(1)		(2)
(i)	Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
(ii)	Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii)	Other places	6.5% of Pay

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.20 per cent of Pay in the first stage of the Scale of Pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) above.

Note.- The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent of House Rent Allowance as hitherto.";

7. In regulation 23 of the said regulations,-

(i) in sub-regulation (1), for the figures, letters and words "1st day of November 2002", the figures, letters and words "1st day of November 2007" shall be substituted;

(ii) in sub-regulation (2), for the figures, letters and words "1st day of November 2002, the figures, letters and words "1st day of November 2007" shall be substituted;

(iii) for sub-regulations (3), (4) and (5), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

"(3) On and from the 1st day of November, 2007, if an officer is serving in an area to be specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.290 per month or Rs.255 per month according to the classification of area as Group A or Group B.

(4) On and from the 1st day of November, 2007, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs.700 per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.

(5) On and from the 1st day of May, 2010, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent of pay subject to a maximum Rs.2300 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank's service at that place:

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs.1200 per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the Bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs.1200 per month.";

(iv) for sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(8) on and from the 1st day of November 2007, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.165 per month.";

(v) in sub-regulation (10),-

(a) for the figures, letters and words "1st day of November 2002", the figures, letters and words "1st day of November, 2007" shall be substituted;

(b) for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

"TABLE

Place (1)	**Rate** (2)
(i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs.550 per month
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2½% of pay subject to a maximum of Rs.680 per month
(iii)Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.1570 per month";

8. In regulation 24 of the said regulations, in sub-regulation (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) Medical Expenses.- On and from the 1st day of November 2007, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:-

IndiaCode

TABLE

Grade	Maximum limit of reimbursement
Junior Management and Middle Management Grade	Rs.5100 or the amount incurred whichever is less
Senior Management and Top Executive Grade	Rs.6320 or the amount incurred whichever is less

Note.- (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above or;

(ii) for the year 2007, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November 2007 and December, 2007.

Explanation. - for the purposes of this regulation,-

(i) hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 100 per cent in the case of an officer and 75 per cent, in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalization or;

(ii) on and from the 1st day of May, 2010, reimbursement of hospitalisation expenses under this regulation shall be in accordance with the terms and conditions of Hospitalisation Scheme as laid down under the Bipartite Settlement dated the 27thday of April, 2010 for workmen employees, subject to the limits as specified in the table below, namely:-

TABLE

(a) Junior Management Grade Scale I and Middle Management Grade Scales II and III.	(i) Bed Charges Self – Rs.700 per day Family – Rs.525 per day (ii) Other charges At the scale of 125% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.
(b) Senior Management Grade Scales IV and V and Top Executive Grade Scales VI and VII.	(i)Bed Charges Self – Rs.900 per day Family – Rs.675 per day (ii) Other charges At the scale of 150% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.”;

IndiaCode

9. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation(1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2007, a sum equal to 1.20 per cent, of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.25 per cent of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.".

10. In regulation 36 of the said regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely :-

"(3) With effect from the 1st day of May 2010, within the overall period of 12 months, leave may also be granted in case of hysterectomy upto a maximum of 45 days.".

11. In regulation 41 of the said regulations, in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

'(a) Halting Allowance – On and from the 1st day of May, 2010, an officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the Table below shall be entitled to `per diem' Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely:-

TABLE

Grades/Scales of officers	**Major `A' Class cities**	**Area I**	**Other Places**
(1)	**(2)**		
	Rs.	**Rs.**	**Rs.**
Officers in Scale IV and above	1000	800	700
Officers in Scale I/II/III	800	700	600

Provided that in the case of officers in Scale IV and above, Halting Allowance payable per diem while on outstation work at the four metros, viz., Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, shall be Rs.1200 and for officers in Scale I or II or III, the per diem Halting Allowance and shall be Rs.1000:

Provided further that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation.- For the purpose of computing Halting allowance "per diem" shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, "per diem" shall mean a period of not less than eight hours.'.

12. In regulation 42 of the said regulations, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(4) On and from the first day of May 2010, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely:-

"TABLE

Grade	Lump Sum
Top Executive and Senior Management	Rs.12,000
Middle Management and Junior Management	Rs.9,000".

IndiaCode

13. In regulation 44 of the said regulations, in sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that with effect from the 1st May 2010, an officer in Junior Management Grade Scale I while availing Leave Travel Concession shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement will be the actual fare or the fare applicable to AC First Class fare by train for the distance traveled, whichever is less and the same rules shall apply to an officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III while availing Leave Travel Concession where the distance is less than 1000 kms.".

14. In regulation 45 of the said regulations, -

(i) in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that there shall be no Provident Fund to Officers joining the services of the Banks on or after the 1st day of April, 2010.";

(ii) in sub-regulation (3), after clause (b) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

"(c) Officers who are covered under the Contributory Provident Fund Scheme who do not opt for Pension Scheme shall continue under the Contributory Provident Fund Scheme.";

(iii) after sub-regulation(3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(4) The officers joining the services of the Bank on or after the 1st day of April 2010 shall be covered by a Defined Contributory Pension Scheme, where the officer shall contribute ten per cent, of pay plus Dearness Allowance and the Bank shall make the similar amount of contribution in accordance with the provisions of the Contributory Pension Scheme in accordance with New Pension Scheme notified by the Central Government vide notification of the Government of India, F.No.5/7/2003-ECB & PR dated the 22nd December, 2003, as amended from time to time."

15. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely,:-

"Schedule to Syndicate Bank (Officers') Service Regulations, 1979

[(See sub-regulation (2) of regulation 23)]

With effect from the 1st day of November, 2007, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.14,700/-	Pay above Rs.14,700/-
1	2	3	4
1.	**Mizoram**		
	(a) Chimptuipui District of Mizoram and areas beyond 25 kms. from Lunglei Town in Lunglei District of Mizoram.	2000	2600
	(b) Throughout Lunglei District excluding areas beyond 25 kms. from Lunglei town of Mizoram.	1600	2100
	(c) Throughout Aizawl District of Mizoram	1200	1500
2.	**Nagaland**	1600	2100
3.	**Andaman and Nicobar Islands**		
	(a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	2000	2600
	(b) South Andaman (including Port Blair)	1600	2100
4.	**Sikkim**	2000	2600
5.	**Lakshadweep Islands**	2000	2600
6.	**Assam**	320	400
7.	**Meghalaya**	320	400
8.	**Tripura**		

IndiaCode

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.14,700/-	Pay above Rs.14,700/-
1	2	3	4
	(a) Difficult areas of Tripura	1600	2100
	(b) Throughout Tripura except difficult areas.	1200	1500
9.	**Manipur**	1200	1500
10.	**Arunachal Pradesh**		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	2000	2600
	(b) Throughout Arunachal Pradesh other than difficult areas.	1600	2100
11.	**Jammu and Kashmir** (a) Kathua District: Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi	2000	2600
	(b) Udhampur District: (i) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, other than those included in Part 2(b).	2000	2600
	(ii) Areas upto Goel from Kamban Side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre.	1600	2100
	(c) Doda District: Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil	2000	2600
	(d) Leh District : All places in the District	2000	2600
	(e) Barmulla District (i) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and KeranIllaqua	2000	2600
	(ii) Matchill	1600	2100
	(f) Poonch and Rajouri District : Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts.	1200	1500
	(g) **Areas not included in items (a) to (f) above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff.**	1200	1500
12.	**Himachal Pradesh**		
	(a) Chamba District		
	(i) Pangi Tehsil, Bharmour Tehsil, Panchayats : Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah, Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata	2000	2600
	(ii) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in item (i) above.	1600	2100
	(iii) Jhandru Panchayat in Bhatiyat Tehsil,Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).	1200	1500

IndiaCode

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.14,700/-	Pay above Rs.14,700/-
1	2	3	4
	(b) Kinnaur District:		
	(i) Asrang, Chitkul and Hango Kuno/ Charang Panchayats,15/ 20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above.	2000	2600
	(ii) Entire District other than Areas included in (a) above.	1600	2100
	(c) Kullu District:		
	(i) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	2000	2600
	(ii) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil and entire District excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand).	1200	1500
	(d) Lahaul and Spiti District :		
	Entire area of Lahaul and Spiti	2000	2600
	(e) Shimla District :		
	(i) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda.	2000	2600
	(ii) Dora-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghori Chaibis of Pargana Sarahan.	1600	2100
	(iii) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, Kasba Rampur and Ghori Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Simla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).	1200	1500
	(f) Kangra District:		
	(i) Areas of Bara Bhangal and Chhota Bhangal	1600	2100
	(ii) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town-Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H. Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Hinwa Project, Shamnagar. Palampur Town of Kangra District including HPKVV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town – H.P. Krishi Vishwavidhalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HESEE Division, Ghuggar.	1200	1500

IndiaCode

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.14,700/-	Pay above Rs.14,700/-
1	2	3	4
	(g) Mandi District: Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in thunag Tehsil- of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja.	1200	1500
	(h) Sirmaur District: Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), BharogBheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil) and Thansgiri Tract	1200	1500
	(i) Solan District : Mangal Panchayat.	1200	1500
	(j) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in items (a) to (i) above.	320	400
13.	**Uttarakhand** Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat Districts.	2000	2600”

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

A STEVEN VAS, General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./362/17]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India on _____ and subsequently amended vide following notifications, namely:-

SL.No.	Gazette Notification No.	Date
1.	16	09.06.1990
2.	16	20.04.1991
3.	23	06.06.1992
4.	29	17.07.1996
5.	44	02.11.1996
6.	47	23.11.2002
7.	24	20.06.2014

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.01.06 14:28:09 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.